भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2350
गुरूवार, 12 मार्च, 2026/21 फाल्गुन, 1947 (शक)

युवा बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की दरें

2350. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युवा (15-29 वर्ष) बेरोजगारी और अल्प-रोजगार की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार दरें क्या हैं;

(ख) शिक्षित युवाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है जिन्हें 'शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं' (एनईईटी) के रूप में वगीकृत किया गया है और पिछले पांच वर्षों के दौरान उसका क्या रुझान है;

(ग) क्या कम शिक्षित युवाओं की तुलना में स्नातकों में अधिक बेरोजगारी देखी गई है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है और उसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) युवाओं में अधिक बेरोजगारी वाले जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान सृजित उद्योगों और गैर-कृषि नौकरियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ड) राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रारंभ से लेकर अब तक युवाओं को प्रदान किए गए प्रशिक्षुता अवसरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है, जिसमें नामांकन, पूर्णता, नियोजन, जारी की गई धनराशि और संवितरित वजीफा शामिल है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, देश में 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 17.8% से घटकर 2023-24 में 10.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2017-18 में 31.4% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गया है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शिक्षा स्तर	**2017-18**	**2023-24**
साक्षर और प्राथमिक तक	8.3	2.6
पूर्व-माध्यमिक	13.7	4.2
माध्यमिक	14.4	4.9
उच्चतर माध्यमिक	21.1	8.8
स्नातक	35.8	25.9
माध्यमिक और उससे अधिक	25.4	15.4

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के लिए बेरोजगारी दर में भी पिछले कुछ वर्षों में कमी आई है। पीएलएफएस रिपोर्टों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और 27 उद्योगों संबंधी रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार वर्ष 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि दर्शाता है।

भारत सरकार, शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत, दो प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन करती है - राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) जिसे अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा वर्ष 2022-23 से एनएपीएस-2 के रूप में जारी रखा गया और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) जिसे शिक्षा मंत्रालय (एमओई) द्वारा वर्ष 1973 में शुरू किया गया और इसे वर्ष 2025-26 तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। साथ में, ये योजनाएं देश भर में शिक्षुता को बढ़ावा देती हैं। कैलेंडर वर्ष 2025 में, एनएपीएस और एनएटीएस के तहत लगे प्रशिक्षुओं की संख्या क्रमशः 11.84 लाख और 5.23 लाख है। कौशल भारत की वेबसाइट https://www.apprenticeshipindia.gov.in/ पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी देखी जा सकती है।

*****